भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या2939

जिसका उत्तर 20 दिसंबर,2023 को दिया जाना है।

29 अग्रहायण, 1945 (शक)

सोशल मीडिया का शासन

2939. श्री पशुपति नाथ सिंहः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी औरसूचना प्रौद्योगिकी मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक की थी जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया को सुरक्षित बनाने और देश में सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नियंत्रित करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख):सरकारकीनीतियोंकाउद्देश्ययहसुनिश्चितकरनाहैकिभारतमेंइंटरनेटखुला, सुरक्षितऔरविश्वसनीयहोतथासभीप्रयोक्ताओंकेप्रतिजवाबदेहहो।

इंटरनेटप्रौद्योगिकीऔरइंटरनेटकोअच्छेकेलिएबलकेरूपमेंदेखाजाताथा, लेकिनहालकेवर्षोंमें, उपयोगकर्ताकोनुकसानपहुंचानेऔरआपराधिकतापैदाकरनेकेलिएप्रौद्योगिकीकाभीदुरूपयोगकियाजाताहै। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या आज 85 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2026 तक 120 करोड़ उपयोगकर्ता होने की उम्मीद है, जिससे भारत वैश्विक इंटरनेट पर सबसे बड़ा कनेक्टेड लोकतंत्र बन जाएगा।सरकारप्रौद्योगिकियोंका लाभ उठानेकेलिएपूरीतरहसेप्रतिबद्धहैलेकिनइसके हानि, जोखिमऔरअपराधोंकीबढ़तीदरसेभी अवगतहै। सरकारयहसुनिश्चितकरनेकाइरादारखतीहैकिइंटरनेटसामान्यरूपसेसुरक्षितहोऔरइसपरजानकारीसुरक्षितऔरविश्वसनीयहोऔरबुरेतत्वोंसेनिपटनेकेलिएनिरंतरआधारपरउपयुक्तकदमउठाती है।

यहसुनिश्चितकरनेकेलिएकिसोशलमीडियाप्लेटफॉर्मसहितमध्यस्थहमेशाउपयोगकर्ताओंकीसुरक्षाऔरविश्वासकेप्रतिजवाबदेहहैं, सरकारनेसंबंधितहितधारकोंकेसाथव्यापकसार्वजनिकपरामर्शकेबादसूचनाप्रौद्योगिकी (मध्यवर्तीदिशानिर्देशऔरडिजिटलमीडियाआचारसंहिता) नियमावली , 2021 ("आईटीनियम, 2021") कोदिनांक 25.02.2021 कोअधिसूचितकियाहैऔरबादमेंइसे सूचनाप्रौद्योगिकीअधिनियम, 2000 ("आईटीअधिनियम")केतहत 28.10.2022 और 6.4.2023 कोसंशोधितकियाहै।

आईटीनियम, 2021 मेंअन्यबातोंकेअलावानिम्नलिखितकानूनीदायित्वोंकोशामिलकियागयाहै:

i. आईटीनियमावली, 2021 केनियम 3 (1) (ख) सोशलमीडियाप्लेटफॉर्मसहितमध्यस्थप्लेटफॉर्मपरउपलब्धभारतीयइंटरनेटपरग्यारहप्रकारकी सामग्रीकोप्रतिबंधितकरताहै।

ii. प्लेटफ़ॉर्मकोयहसुनिश्चितकरनेकीआवश्यकताहैकिउनकेउपयोगकर्तानियम 3 (1) (ख) औरअन्यकानूनोंकाउल्लंघनकरनेवालीसामग्रीकोसाझाकरनेयाप्रसारितकरनेकेलिएअपनेप्लेटफ़ॉर्मकाउपयोग न करेंऔरउनकेउपयोगकीशर्तेंकानूनकेतहतग्यारहप्रकारकीसामग्रीकेउपयोगकोस्पष्टरूपसेप्रतिबंधितकरती हैं।

iii. आईटीनियमावली, 2021 केनियम 3 (1) (ख) (ii) मेंऐसीकिसीभीजानकारीकोप्रतिबंधितकियागयाहैजोअश्लील, पोर्नोग्राफ़िक, पीडोफिलिक, शारीरिकगोपनीयतासहितकिसीअन्यकीगोपनीयताकेखिलाफहै।

iv. आईटीनियमावली, 2021 केनियम 3 (1) (ख) (v) और (vi) भारतीयइंटरनेटपरगलतसूचनाऔरस्पष्टरूपसेझूठीजानकारीयाकिसीअन्यव्यक्तिकाप्रतिरूपण करने वाली जानकारीकोप्रतिबंधितकरतेहैं ।डीपफेकएआई द्वारासंचालितगलतसूचनाकाएकऔररूपहै।

v. आईटीनियमावली , 2021 केनियम 3 (1) (घ) मेंप्लेटफार्मोंकोआईटीनियम, 2021 केतहतनिर्धारितसमयसीमाकेभीतरउपयुक्तसरकारयाउसकीअधिकृतएजेंसीसेअदालतकेआदेशयाअधिसूचनाप्राप्तहोनेपरयाइससंबंधमेंउसकेद्वाराअधिकृतव्यक्तियाव्यक्तिद्वाराकीगईशिकायतपरआईटीनियम, 2021 केउपरोक्तप्रावधानोंका उल्लंघन करने वाली सूचना/सूचना सामग्री तकपहुंचकोहटानेयाअक्षमकरनेकेलिएअधिदेशितकियागयाहै ।

vi. आईटी नियमावली, 2021 के नियम 4(2) में यह निर्धारित किया गया है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, या सार्वजनिक व्यवस्था, या उपरोक्त से संबंधित अपराध के लिए उकसाना या बलात्कार, स्पष्ट यौन सामग्री या बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) के संबंध मेंसंबंधित जानकारी के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करके रोकथाम, पता लगाने, जांच, अभियोजन या सजा के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ सहयोग करेंगे।

आईटी नियम, 2021 विशिष्ट कानूनी दायित्व निर्धारित करता है और सोशल मीडिया मध्यस्थों या प्लेटफार्मों सहित मध्यस्थों पर जवाबदेही डालता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके प्लेटफार्म सुरक्षित और

विश्वसनीय हों और उनपर नियम 3(1) का उल्लंघन करने वाली कोई भी सामग्री न हो जिसमें प्रतिबंधित बेहुदापन, अश्लीलता, गलत सूचना, स्पष्ट रूप से गलत जानकारी और डीपफेक को हटाने की दिशा में उनकी

त्वरित कार्रवाई शामिल है।चूंकिसोशलमीडियासहितसभीमध्यस्थप्लेटफार्मोंपरजवाबदेहीस्पष्टरूपसेडाली गईहैऔरयदिकोईमध्यस्थआईटीनियम, 2021 काउल्लंघनकरताहै, तोवेसूचनाप्रौद्योगिकीअधिनियम, 2000 ("आईटीअधिनियम") कीधारा 79 केतहतअपनीसेफ़ हार्बर सुरक्षाखोदेंगेऔरआईटीअधिनियमऔरभारतीयदंडसंहितासहितकिसीभीकानूनकेतहतप्रदानकीगईपरिणामीकार्रवाईयाअभियोजनकेलिएउत्तरदायीहोंगे।

सरकारडिजिटलइंडियासंवाद (“डीआईडी”) केमाध्यमसेसार्वजनिकपरामर्शकाउपयोगसमय-समयपरविभिन्नविचारोंकापतालगानेकेलिएडिजिटलइकोसिस्टम
केसभीहितधारकोंकेसाथजुड़नेकेएकमहत्वपूर्णतरीकेकेरूपमेंकरतीहै।
हरकानूनऔरहरनियमकोसार्वजनिकपरामर्शकेसाथविकसितकियागयाहै।

(ग) और (घ): यह सुनिश्चित करने के लिए कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित मध्यस्थ हमेशा उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और विश्वास के प्रति जवाबदेह हों, सरकार ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बाद 25.02.2021 को अधिसूचित आईटी नियम, 2021 निर्धारित किए हैं और बाद में 28.10.2022 और 6.4.2023 को इन्हें संशोधित किया है, जो प्लेटफार्मों या मध्यस्थों पर गंभीर कानूनी दायित्व डालते हैं कि वे आईटी नियम, 2021 के नियम 3 (1) (ख) के तहत निषिद्ध ग्यारह प्रकार की सामग्री में उल्लिखित सामग्री को होस्ट या साझा न करें और उपयोगकर्ताओं को ऐसी किसी भी सामग्री को होस्ट या साझा करने से रोकें।

इसके अलावा, सरकार समय-समय पर किसी भी राष्ट्र-विरोधी सामग्री या राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को हटाने के लिए मंच को निर्देशित करने के लिए आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 क के तहत अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करती है।

****